

भारत का सामरिक पेट्रोलियम भंडार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान [सामरिक पेट्रोलियम भंडार](#) कार्यक्रम में बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार:

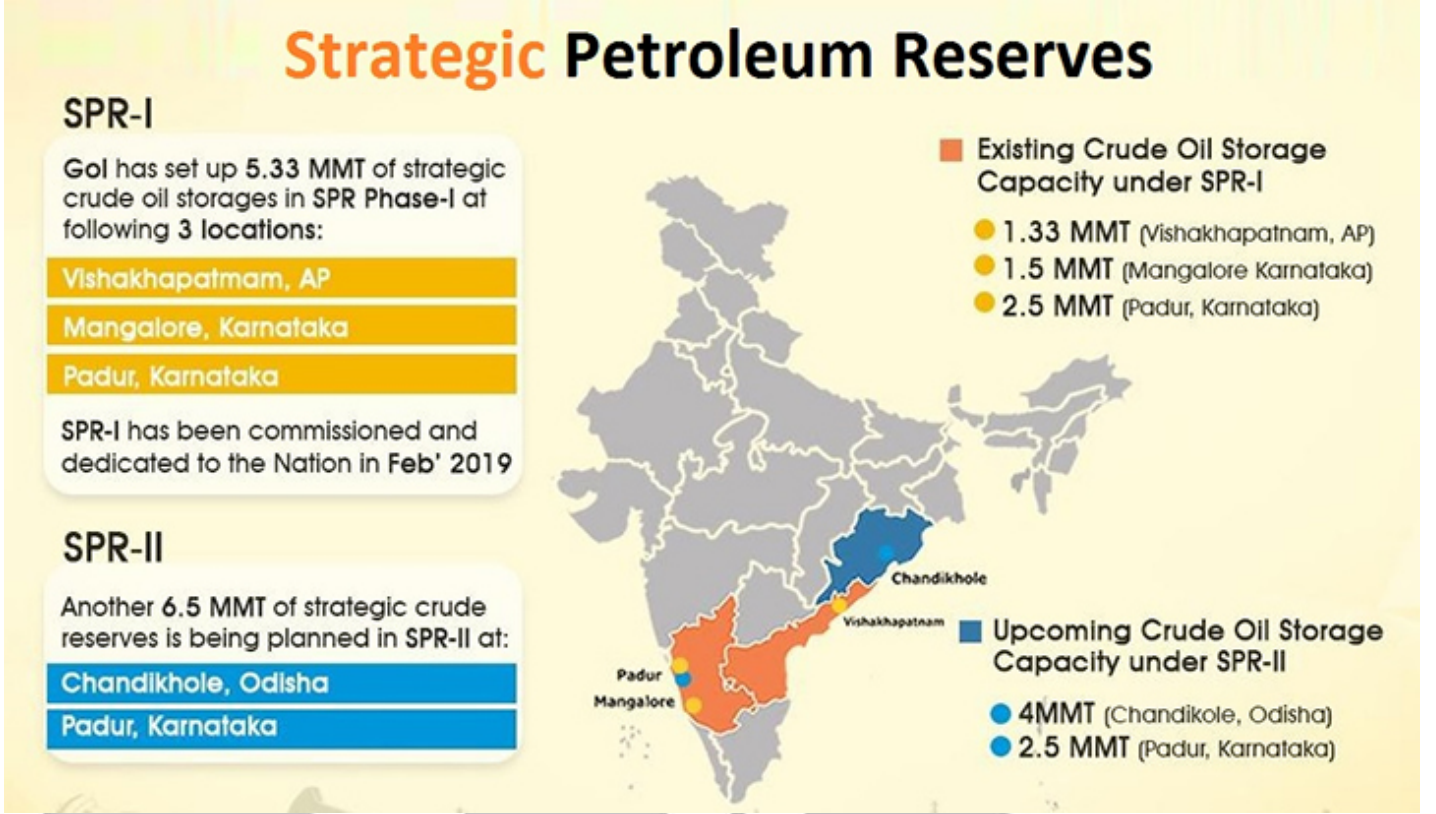
परिचय:

- सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) [कच्चे तेल](#) के वे भंडार हैं जिन्हें भू-राजनीतिक अनश्चितता या आपूर्ति व्यवधान के समय में कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले देशों द्वारा बनाए रखा जाता है।
- देश की वृद्धि और विकास के लिये ऐसी भूमिगत भंडारण सुविधाएँ [ऊर्जा संसाधनों के नरिंतर प्रवाह](#) को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

नोट:

- अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा कार्यक्रम (International Energy Programme- IEP) पर समझौते के अनुसार, कम-से-कम 90 दिनों के लिये शुद्ध तेल आयात के बराबर आपातकालीन तेल का स्टॉक रखना [अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी \(International Energy Agency- IEA\)](#) के प्रत्येक सदस्य देश का दायित्व है।
- गंभीर तेल आपूर्ति व्यवधान के मामले में IEA सदस्य सामूहिक कार्रवाई के हिससे के रूप में इन शेरों को बाज़ार में जारी करने का नरिणय ले सकते हैं।
- भारत वर्ष 2017 में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) का सहयोगी सदस्य बना।
- भारत में वर्तमान SPR अवसंरचना और क्षमता:
 - इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रजिस्ट्रार लिमिटेड (ISPRL) को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक [वशिष प्रयोजन वाहन](#) के रूप में बनाया गया था।
 - भारत में कच्चे तेल की मौजूदा भूमिगत SPR सुविधाओं की संयुक्त धारिता 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) है। ये भंडारण स्थल रणनीतिक रूप से दो राज्यों में स्थिति हैं:
 - वशिषाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश - 1.33 MMT धारिता
 - मंगलुरु, कर्नाटक - 1.5 MMT धारिता
 - पादुर, कर्नाटक - 2.5 MMT धारिता
- संभरण रणनीति:
 - अप्रैल-मई 2020 में कच्चे तेल की कम कीमतों से प्राप्त हुए अवसर का लाभ उठाते हुए, भारत ने अपनी मौजूदा SPR सुविधाओं में सफलतापूर्वक पूरा धारिता का संभरण किया है।
 - इस सामरिक कदम के परिणामस्वरूप पर्याप्त बचत हुई, जिसका अनुमान लगभग 5000 करोड़ रूपए था।
- वसितार योजनाएं और वाणजियिक-सह-रणनीतिक केंद्र:
 - जुलाई 2021 में, भारत सरकार ने दो अतिरिक्त वाणजियिक-सह-रणनीतिक SPR केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी।
 - चंडीखोल, ओडिशा- 4 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता
 - पादुर, कर्नाटक - 2.5 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता (वसितार)
 - कुल 6.5 मिलियन मीट्रिक टन भंडारण क्षमता वाले ये केंद्र सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड के तहत संचालित होंगे।
- स्थानांतरण और समयरेखा:
 - 60 वर्ष की छूट रियायत की अवधि समाप्त होने पर, रियायतग्राही सगिल मूरगि पॉइंट्स (SPM) और ऑनशोर/ऑफशोर पाइपलाइनों जैसे बुनियादी अवसंरचना और SPR को भारत सरकार को वापस स्थानांतरित कर देगा।
- रजिस्ट्रार का इतिहास:
 - वर्ष 1990 में पश्चिम एशिया में खाड़ी युद्ध के दौरान, भारत एक बड़े ऊर्जा संकट से जूझ रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि इसके मौजूदा तेल भंडार केवल तीन दिनों के लिये पर्याप्त हैं।

- हालाँकि भारत ने उस समय इस संकट को सफलतापूर्वक टाल दिया था, लेकिन ऊर्जा व्यवधान का खतरा आज भी एक वास्तविक और नरिंतर चिंता बनी हुई है।
- इस ऊर्जा असुरक्षा से निपटने के प्रयास में अटल बहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले प्रशासन ने वर्ष 1998 में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार स्थापित करने का विचार सामने रखा।
 - वर्तमान समय में, जैसे-जैसे भारत में ऊर्जा की खपत बढ़ती जा रही है, ऐसे भंडार विकसित करने की प्रासंगिकता भी बढ़ती जा रही है।
- विश्व में सबसे बड़े वैश्विक रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार हैं:
 - संयुक्त राज्य अमेरिका- 714 मिलियन बैरल
 - चीन- 475 मिलियन बैरल
 - जापान- 324 मिलियन बैरल



//

स्रोत: पी.आई.बी.